# "टोकियो घोषणा" 2014 की समीक्षा: भारत के प्रधानमंत्री की जापान यात्रा का सार

डॉ. शमशाद ए. खान*

भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पांच-दिवसीय जापान यात्रा, जो 3 सितंबर, 2014 को समाप्त हुई, के दौरान भारत और जापान ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई ऊंचाई तक ले जाने के विभिन्न उपायों की घोषणा की है। उन्होंने सहयोग के क्षेत्रों की पहचान की है, विशेषकर आर्थिक दायरे में, जहां वे एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। जहां जापान ने आगामी पांच वर्षों के दौरान भारत में 35 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश की घोषणा की है, वहीं भारत ने जापानी निवेशकों के लिए *'रेड कार्पेट'* बिछाने का वायदा किया है। जापान अपनी निर्यात-उन्मुख आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने के लिए उच्च तकनीक वाले उत्पादों का उत्पादन करना चाहता है; भारत ने जापान को दुर्लभ भू-खनिज का प्रस्ताव दिया है, जो इन उत्पादों के विनिर्माण में महत्वपूर्ण है। भारत अपनी आर्थिक विकास की गति तेज करने के लिए हाई-स्पीड रेल नेटवर्क, पत्तन तथा समर्पित माल-भाड़ा कॉरिडोर सहित विश्व स्तर की अवसंरचना चाहता है; जापान इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत को हाई-स्पीड रेल प्रौद्योगिकी तथा पूंजी प्रदान करने पर सहमत हो गया है। इन वायदों के अलावा, जापान भारत के कुछ रक्षा तथा अंतरिक्ष उद्यमों को अपने "एंड यूजर लिस्ट" से हटाने पर सहमत हो गया है। इस सूची के अनुसार, चुनिन्दा भारतीय उद्यम जापानी कम्पनियों से प्रौद्योगिकी प्राप्त करने अथवा व्यापार वार्ता करने से प्रतिबंधित हैं।

यह मुद्दा सार, जिसमें प्रधानमंत्री स्तर की शिखर वार्ताओं के अंत में जारी संयुक्त विज्ञप्ति और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जापान में दिए गए चुनिंदा भाषणों का विश्लेषण दिया गया है, कुछ प्रमुख वायदों को रेखांकित करता है जो भारत-जापान द्विपक्षीय संबंधों को और घनिष्ठ बनाने के लिए दोनों देशों के नेतृत्व ने किया है।

**भारत-जापान रणनीतिक भागीदारी: भूतकाल से वर्तमान काल तक**

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की जापान यात्रा और अपने समकक्ष सिंजो आबे के साथ इनकी बातचीत वर्ष 2006 में स्थापित प्रधानमंत्री स्तरीय वार्ता के क्रम में थी। वर्ष 2006 में रणनीतिक भागीदारी पर हस्ताक्षर करते समय भारत व जापान नई दिल्ली और टोकियो में बारी-बारी से प्रत्येक वर्ष शिखर स्तरीय वार्ता आयोजित करने पर सहमत हुए थे।

यह उल्लेखनीय है कि भारत-जापान संबंध अपने द्विपक्षीय संबंधों में रूकावट के कई चरणों का साक्षी बना है, जिसमें वर्ष 1998 का पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद (की रूकावट) शामिल है, जिसके दौरान दोनों देशों के बीच राजनैतिक संपर्क सुसुप्त रहे। शिखर-स्तरीय वार्ता संपर्क की स्थापना ने इस रूझान को पलट दिया है। नि:संदेह, प्रधानमंत्री स्तरीय वार्ता, जो वर्ष 2006 से लगभग बिना किसी रूकावट के होती रही है, ने द्विपक्षीय संबंधों को एक रणनीतिक भागीदारी में बदल दिया है। रणनीतिक भागीदारी के भाग के रूप में, दोनों ही देशों ने द्विपक्षीय हितों के कई क्षेत्रों की पहचान की है, जिनमें वे परस्पर सहयोग कर रहे हैं। इनमें व्यापार, अर्थशास्त्र, अवसंरचना, सुरक्षा एवं रक्षा तथा ऊर्जा सुरक्षा शामिल हैं।

जापान भारत के साथ इस पूरक संबंध को जारी रखने और इसे प्रगाढ़ बनाने के लिए उत्सुक था और उसने नए भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को निमंत्रण भेजने में तनिक भी देरी नहीं की। वह उनके (नरेन्द्र मोदी के) कार्यकाल संभालने के पश्चात उनका पहला विदेशी मेजबान बनने को उत्सुक था। तथापि, भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने विदेश दौरों के लिए भूटान और नेपाल सहित पड़ोसी देशों को चुना। घरेलू व्यस्तताओं के कारण दो बार अपनी जापान यात्रा पुन:निर्धारित करने के पश्चात भारतीय प्रधानमंत्री 30 अगस्त से प्रारंभ होने वाली अपनी पांच दिवसीय सरकारी यात्रा पर जापान गए। जापानी प्रधानमंत्री ने "भारत के निकट पड़ोस से बाहर द्विपक्षीय दौरे के लिए अपने प्रथम गंतव्य"[2] के रूप में जापान का चयन करने पर "हार्दिक सराहना व्यक्त की।"[1] यह वक्तव्य भारत-जापान संबंधों को गहरा बनाने की दिशा में जापान की संतोषपूर्ण भावना प्रदर्शित करता है।

इस यात्रा के दौरान, भारत-जापान द्विपक्षीय संबंधों के पुराने एजेंडे: व्यापार तथा आर्थिक संबंधों का विस्तार; प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, अवसंरचनात्मक क्षेत्र में सहयोग; रेल, सड़क तथा पत्तन सुविधाओं के विकास के साथ-साथ असैनिक परमाणु सहयोग आदि (एजेंडे में) प्रमुख थे। चूंकि पहले से तय कुछ मुद्दे अभी फलीभूत नहीं हुए हैं, इसलिए इन मुद्दों पर परामर्शों को आगे बढ़ाने और इन्हें तार्किक परिणाम तक ले जाने की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था बुद्धिमानीभरी राणनीति थी। फिर भी, नए एजेंडे में, विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी के सपनों की कुछ परियोजनाएं भी इस यात्रा के दौरान सामने आईं और द्विपक्षीय सहयोग

का हिस्सा बन गईं। ऐसे कुछ एजेंडों पर नीचे चर्चा की गई है:

**द्विपक्षीय रणनीतिक भागीदारी को नया आयाम देना**

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जापान यात्रा के प्रमुख परिणामों में से एक है – मौजूदा रणनीतिक भागीदारी को एक "विशेष" रणनीतिक तथा वैश्विक भागीदारी तक ले जाना।[3] वर्तमान में, भारत ने 29 देशों तथा क्षेत्रीय समूहों के साथ रणनीतिक भागीदारियों पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि प्रयुक्त शब्दावलियां थोड़ी भिन्न हैं। इस शिखर सम्मेलन की बैठक से पहले भारत ने यह विशेष "दर्जा" केवल रूस[4] को दिया है, जिसके साथ इसके परंपरागत तथा समय की कसौटी पर खरे संबंध हैं। रूस को दिए गए दर्जे के समान दर्जा जापान को देना यह संकेत देता है कि भारत इस पूर्वी एशियाई देश के साथ अपने संबंधों को सर्वोच्च महत्व देता है और आने वाले दशकों में टोकियो नई दिल्ली की प्राथमिकताओं के शिखर पर बना रहेगा। जापान भी जापानी विदेश तथा रक्षा मंत्रालयों और उनके भारतीय समकक्षों के बीच मौजूदा 2+2 वार्ता का स्तर बढ़ाकर इसे रक्षा तथा विदेश मंत्रियों के स्तर तक लाने के लिए उत्सुक था। इस समय भारत और जापान के बीच 2+2 वार्ता दोनों सरकारों के सर्वोच्च नौकरशाहों के स्तरों पर होती है। भारत तथा जापान के प्रधानमंत्रियों के बीच शिखर बैठक के अंत में जारी वक्तव्य में उल्लेख है कि दोनों नेताओं ने "अपनी बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के लिए विदेश तथा रक्षा सचिवों के स्तर की 2+2 वार्ता के महत्व को रेखांकित किया और इस वार्ता में तेजी लाने के मार्ग तलाशने का निर्णय किया।"[5] तथापि, यह वक्तव्य इस वार्ता का स्तर बढ़ाने की घोषणा करने के स्तर तक नहीं पहुंच सका। जापानी मीडिया ने भारत के प्रधानमंत्री की हाल की यात्रा के दौरान इस वार्ता का स्तर बढ़ाने में भारत की अनिच्छा की व्याख्या अलग तरीके से की है। "चीन के प्रति चिन्ता स्पष्टत: प्रमुख बाधा थी।"[6] *अशही सिम्बुन* ने टिप्पणी की। इसी प्रकार, *मेनीची डेली* का विश्लेषण था कि यह दौरा "बिना किसी ऐसी उच्च स्तरीय सुरक्षा वार्ताओं के समाप्त हुआ जैसी कि जापान द्वारा मांग की गई थी, जो चीन को उकसाने से बचने हेतु भारत की चाल हो सकती है।"[7] तथापि, टैम्पल विश्वविद्यालय में सीरियाई अध्ययन के निदेशक जेफ किंगटन के विचार भिन्न हैं: "इस बात की अधिक संभावना प्रतीत होती है कि भारत अधिक विस्तृत वार्ताओं हेतु मोल-तोल के दांव के रूप में 2+2 सौदे को लटका रहा है।"[8] यह भारत का मोल-तोल दांव अथवा चीन फैक्टर था या नहीं, जो राजनीतिक वार्ता का स्तर बढ़ाने के विचार में बाधक बना, इस तथ्य से परे दोनों देशों को अभी भी नए फ्रेमवर्क स्थापित करने से पहले कुछ आधारभूत कार्य करने की जरूरत है।

**आर्थिक संबंधों को नए सिरे से आगे बढ़ाना**

यद्यपि भारत और जापान एक दीर्घकालिक राजनीतिक भागीदारी के बारे में सोच रहे थे, तथापि, उन्होंने निश्चित किया कि यह "अर्थव्यवस्था" ही है जिसे संबंधों की नीव का सबसे सुदृढ़ स्तंभ बनाना चाहिए। वर्ष

2006 में एक संयुक्त वक्तव्य में भारत और जापान ने पुष्टि की थी कि "एक सुदृढ़ एवं संपन्न भारत जापान के हित में है और एक सुदृढ़ संपन्न जापान भारत के हित में है।" दोनों ने आपसी द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के तरीके की पहचान की जो उस समय अत्यंत ही कम, लगभग छह अरब मिलियन अमरीकी डॉलर था। उन्होंने एक दूसरे के निवेशकों के लिए उपयुक्त वातावरण सृजित करने का निर्णय किया और वर्ष 2011 में लम्बी बातचीत के बाद व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए) को अंतिम रूप दिया। आर्थिक भागीदारी के भाग के रूप में, दोनों (देशों) ने दोनों देशों के बीच कारोबार से संबंधित लगभग 90 हजार सामानों पर लगे प्रशुल्कों को धीरे धीरे कम करने का निर्णय लिया और एक दूसरे के निवेशकों को "राष्ट्रीय सत्कार" (का स्तर) प्रदान किया। प्रशुल्क कम करने की रणनीति से द्विपक्षीय व्यापार का प्रवाह तेज हुआ और सीईपीए के लागू किए जाने के एक वर्ष के भीतर ही द्विपक्षीय व्यापार में राजकोषीय वर्ष 2012 के अंत तक 18 अरब अमरीकी डॉलर का उछाल आया जो राजकोषीय वर्ष 2011 के अंत में 12 अरब अमरीकी डॉलर था। तथापि, द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा/पैमाना अगले राजकोषीय वर्ष के दौरान अनुमानित 25 अरब अमरीकी डॉलर तक नहीं पहुंचा बल्कि यह घटकर 16 अरब अमरीकी डॉलर तक आ गया है।

इसी प्रकार, व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए) के बाद जापानी निवेश में अत्यधिक वृद्धि की प्रत्याशा थी लेकिन यह धीमी गति से बढ़ रहा है। अबतक लगभग 1100 जापानी कम्पनियों ने भारत में अपने उत्पादन स्थल/बेस स्थापित किए हैं जबकि यह संख्या चीन में लगभग 8000 है। वर्ष 2011 में व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए) को अंगीकार करके व्यापार मानकों को आसान बनाने के बावजूद, जापानी निवेशक भारतीय बाजारों से हट रहे हैं और अपनी पूंजी इंडोनेशिया, वियतनाम और फिलिपिन्स के बाजारों में झोंक रहे हैं। जापानी निवेशकों की समस्याओं को भांपते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल में समाप्त हुए दौरे के दौरान उन्हें आश्वस्त किया है कि भारत जापानी निवेशकों के लिए 'लालफीताशाही' को 'रेड कार्पेट' से बदल रहा है। टोकियो में जापानी उद्यमियों के समूह को संबोधित करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री ने उन्हें सूचित किया कि भारत ने एक "आसान व्यापार" की नीति अपनाई है।[9] उन्होंने उनके सामने "मेक इन इंडिया" मंत्र की व्याख्या की और जापानी व्यापारियों को आश्वस्त किया कि भारत में निवेशकों के लिए विशाल अवसर हैं। अपने "थ्रि डी मंत्र" की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि भारत न केवल विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि यहां बड़ी *जनसंख्या* और *मांग* भी है। चूंकि भारत के लोग नौजवान हैं इसलिए लंबे समय तक सामानों की उच्च मांग बनी रहेगी और इस प्रकार भारत एक ऐसी स्थली हो सकती है जहां जापानी निवेशक अपना भविष्य बना सकते हैं। विश्व के मानचित्र पर भारत की भू-रणनीतिक अवस्थिति का वर्णन करते हुए उन्होंने सूचित किया कि यदि वे (जापानी व्यापारी) भारत को अपनी विनिर्माण स्थली बना लें तो वे न केवल भारतीय बाजार में अपने निर्मित उत्पादों को बेच सकते हैं

बल्कि भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों के आसपास स्थित इसके पत्तनों के रास्ते विभिन्न एशियाई तथा अफ्रीकी देशों को इनका निर्यात भी कर सकते हैं।[10]

इस यात्रा के दौरान, जापान आगामी पांच वर्षों के दौरान भारत के लिए ऋणों तथा निवेश हेतु 35 अरब अमरीकी डॉलर निर्धारित/निश्चित करने पर सहमत हो गया है। नि:संदेह इससे भारत को अपनी अवसंरचना में सुधार करने में सहायता मिलेगी जो पर्यवेक्षकों का मानना है कि, इस देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित करने में आने वाली बाधाओं में से एक रहा है। इसके अलावा, भारत मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन प्रौद्योगिकी प्रारंभ करने पर सहमत हो गया है और जापानी पक्ष ने "*सिंकान्सेन* प्रणाली प्रारंभ करने हेतु वित्तीय, तकनीकी तथा प्रचालनात्मक समर्थन प्रदान करने में अपनी तत्परता"[11] प्रदर्शित की है। हालांकि, इस प्रौद्योगिकी को प्रारंभ करने में अभी कुछ और समय लगेगा क्योंकि भारतीय तथा जापानी विशेषज्ञों द्वारा पिछले वर्ष प्रारंभ किया गया संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन पूरा होना अभी बाकी है। मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन की सफलता निश्चित रूप से भारत के विभिन्न बड़े शहरों के बीच इस प्रौद्योगिकी को प्रारंभ करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। दोनों देशों ने जापान की प्राचीन राजधानी क्योटो की तर्ज पर वाराणसी को "स्मार्ट सिटी" बनाने संबंधी एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। आशा है कि वाराणसी की सफलता की कहानी और इस प्रक्रिया के दौरान सीखे गए कौशल को भारत के विभिन्न प्राचीन शहरों पर भी आजमाया जाएगा।

रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संयुक्त सहयोग की दिशा में भी कुछ सफलता प्राप्त की गई। सबसे महत्वपूर्ण बात, जापान ने अपनी "एण्ड यूजर्स लिस्ट"[12] से कुछ भारतीय रक्षा उद्यमों को हटा दिया है जिससे जापानी तथा भारतीय कंपनियों के बीच संयुक्त रक्षा उत्पादन का मार्ग प्रशस्त होगा और इससे रक्षा व्यय कम करने में मदद मिलेगी। भारत रक्षा प्रौद्योगिकीय क्षेत्र में जापान का भागीदार बनने का इच्छुक है, तथापि रक्षा तथा रक्षा संबंधी प्रौद्योगिकी का निर्यात करने पर दशक-पुराने स्व-अधिरोपित प्रतिबंध के चलते जापान उदासीनता दिखला रहा था। कुछ महीने पहले सिंजो आबे के मंत्रिमंडल ने इन प्रतिबंधों में कुछ छूट दी तथापि, भारत द्वारा यूएस-2 महत्वकांक्षी एयरक्राफ्ट के प्रापण/खरीद पर गतिरोध जारी है। यह एयरक्राफ्ट उन्नत हवाई-समुद्री अनुसंधान एवं बचाव अभियानों के लिए विश्व में उपलब्ध अपने प्रकार का एकमात्र एयरक्राफ्ट है जो अस्थिर समुद्र के साथ-साथ भूमि पर भी उतर सकता है। टोकियो नई दिल्ली को यूएस-2 एयरक्राफ्ट बेचना चाहता है, लेकिन नई दिल्ली इसका उत्पादन संयुक्त रूप से करना चाहता है क्योंकि एक यूएस-2 एयरक्राफ्ट की लागत लगभग 109 अरब अमरीकी डॉलर है। ऐसी अटकलें थीं कि संयुक्त सहयोग हेतु अनुमति दिए जाने संबंधी घरेलू कानूनों में बदलावों को देखते हुए यूएस-2 के संयुक्त उत्पादन के लिए जापान अपनी कंपनियों को हरी झंडी दे देगा, लेकिन दोनों देश किसी करार पर नहीं पहुंच सके। तथापि, संयुक्त वक्तव्य में "यूएस-2 महत्वकांक्षी अमरीकी एयरक्राफ्ट और इसकी प्रौद्योगिकी में सहयोग पर संयुक्त

कार्य समूह की चर्चाओं में हुई प्रगति का स्वागत किया गया और अपने-अपने अधिकारियों को उनकी चर्चाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।"[13]

भारत में जापानी निवेश आकर्षित करने के लिए, नई राजनीतिक व्यवस्था ने इस यात्रा के दौरान कुछ नए उपायों की घोषणा की है जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत एक नई इकाई स्थापित करने की घोषणा की है, जो भारत में जापानी निवेश को सुविधाजनक बनाएगी।[14] लेकिन राजनीतिक प्रतिबद्धता को मूर्त रूप केवल तभी दिया जा सकता है जब इसे इसके उद्यमियों तथा निवेशकों का समर्थन मिले। यह देखना अभी बाकी है कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर जापानी उद्यमी कैसी प्रतिक्रिया दिखलाते हैं।

इस यात्रा के दौरान, भारतीय प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच संबंधों को घनिष्ठ बनाने हेतु जापानी नेताओं से एक नया राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाने का भी आह्वान किया। उन्होंने जापानी नेताओं को भारत की "पूर्वोन्मुख नीति"[15] की तर्ज पर "भारत उन्मुख" नीति तैयार करने के लिए समझाया। उन्होंने यह भी कहा कि "भारत जापान के बिना अधूरा है और जापान भारत के बिना अधूरा है।"[16] यह वक्तव्य वर्ष 2006 की प्रतिबद्धता के सदृश्य है, जिसमें उन्होंने पाया था कि सुदृढ़ और संपन्न भारत और जापान एक दूसरे के हित में है।

**असैनिक परमाणु सहयोग: गतिरोध जारी**

भारत-जापान के कुछ सफल वृतांत के बावजूद, जापान के साथ परमाणु सहयोग करार पर हस्ताक्षर किया जाना अभी भी एक अधूरा एजेंडा है। जापान के साथ यह अधूरा पड़ा करार भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तथापि, जापान अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर न करने वाले किन्हीं देशों को परमाणु प्रौद्योगिकी बेचने की विरोधी अपनी जनता की चिन्ताओं के कारण, भारत के साथ परमाणु सहयोग सौदे पर हस्ताक्षर करने में अत्यंत सावधानी बरत रहा है। उम्मीद थी कि जापानी प्रधानमंत्री आबे, जो परमाणु प्रौद्योगिकी सहित प्रौद्योगिकियां बाहरी देशों को बेचा जाना जापानी अर्थव्यवस्था के पुनरूद्धार का एक महत्वपूर्ण स्तंभ मानते हैं, वे लंबित असैनिक परमाणु करार कर ही लेंगे। उन्होंने अपने संयुक्त वक्तव्य में उल्लेख किया कि दोनों प्रधानमंत्रियों ने "इस करार को शीघ्र ही अंतिम रूप देने के विचार से अपने-अपने अधिकारियों को वार्ताओं में और तेजी लाने के निदेश दिए।"[17] पिछले कुछेक वर्षों में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनके जापानी समकक्षों के बीच हस्ताक्षरित संयुक्त वक्तव्य में परमाणु सहयोग के बारे में इसी प्रकार की टिप्पणियां की गई हैं। परमाणु सहयोग करार पर दोनों देशों के बीच इसी प्रकार के जारी वक्तव्य सुझाते हैं कि अपनी-अपनी धारणाओं को दूर करने के लिए उन्हें अभी और कुछ करना बाकी है।

## निष्कर्ष

नि:संदेह, मेट्रो रेल सहित प्रोद्योगिकियां तथा ऋण प्रदान करके भारत को अपनी अवसंरचना में सुधार करने में जापान के सहयोग ने भारत के शहरी परिदृश्य को परिवर्तित कर दिया है। आशा है कि भारतीय प्रधानमंत्री की हाल की जापान यात्रा के दौरान किया गया वायदा अक्षरश: कार्यान्वित किया जाएगा। भारत और जापान के बीच संबंधों की पूरक प्रकृति एशियाई क्षेत्र को एक संपन्न और शांतिपूर्ण क्षेत्र बनाने में मार्गदर्शक बनेगी। साथ ही, उम्मीद है कि दोनों देश असैनिक परमाणु सहयोग करार, जो भारत-जापान आर्थिक संबंधों को एक नया प्रोत्साहन प्रदान करेगा, के गतिरोध पर एक दूसरे के रूख से सामंजस्य बिठाते हुए सहमति पर पहुंच जाएंगे।

* डॉ. *शमशाद ए खान, विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली में अनुसंधान अध्येता हैं।*

## समाप्ति नोट:

[1] "भारत-जापान विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक भागीदारी के लिए टोकियो घोषणापत्र", 1 सितंबर, 2014, *भारत का विदेश मंत्रालय,* http://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/23965/Tokyo+Declaration+for+India++Japan+Special+Strategic+and+Global+Partnership पर उपलब्ध ( 3 सितंबर, 2014 को एक्सेस किया गया)।

[2] पूर्वोक्त।

[3] पूर्वोक्त।

[4] रूस के साथ भारत की रणनीतिक भागीदारी को "विशेष और विशेषाधिकार-प्राप्त रणनीतिक भागीदारी" का नाम दिया गया है।

[5] पूर्वोक्त।

[6] "जापान, भारत करार की राह में आया चीन", *द असाही शिम्बुन,* 2 सितंबर, 2014. http://ajw.asahi.com/article/behind_news/politics/AJ201409020042 पर उपलब्ध (2 सितंबर, 2014 को एक्सेस किया गया) ।

[7] "मोदी का दौरा जापान, भारत के बीच उच्च स्तरीय सुरक्षा रूपरेखा लाने में असफल रहा", *द मैनिची डेली,* 2 सितंबर, 2014, http://mainichi.jp/english/english/newsselect/news/20140902p2a00m0na017000c.html पर उपलब्ध (2 सितंबर, 2014 को एक्सेस किया गया)।

[8] जेफ किंग्सटन, "मोदी की यात्रा के दौरान शोमैन के तुरूप का इक्का", *द जापान टाइम्स,* 6 सितंबर, 2014

[9] निक्केई इंक. और जापान विदेश व्यापार संगठन (जेट्रो) द्वारा आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री के मुख्य भाषण का पाठ, 2 सितंबर, 2014, *भारत के प्रधानमंत्री का कार्यालय,* http://pmindia.gov.in/en/news_updates/text-of-pms-keynote-address-at-event-organized-by-nikkei-inc-and- japan-external-trade-organization-jetro-2/ पर भाषण का संपूर्ण पाठ उपलब्ध ( 5 सितंबर, 2014 को एक्सेस किया गया)।

[10] पूर्वोक्त।

[11] "भारत – जापान विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक भागीदारी के लिए टोकियो घोषणापत्र", उद्धरण संख्या 1 के सन्मुख।

[12] पूर्वोक्त।

[13] पूर्वोक्त।

[14] "मोदी के प्रधानमंत्री कार्यालय के विशेष दल में जापानी लोग", *द इकोनॉमिक टाइम्स,* 2 सितंबर, 2014

[15] निक्केई इंक. और जापान विदेश व्यापार संगठन (जेट्रो) द्वारा आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री के मुख्य भाषण का पाठ, उद्धरण संख्या 8 के सन्मुख।

[16] पूर्वोक्त।

[17] ""भारत-जापान विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक भागीदारी के लिए टोकियो घोषणापत्र", 1 सितंबर, 2014", उद्धरण संख्या 1 के सन्मुख।